जैव विविधता को बचाने के प्रयास शुरू

सन 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया है और इसी के चलते इस वर्ष की शुरुआत से ही जैव विविधता को बचाने के लिए बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। 18-20 जनवरी को लंदन में हुई मीटिंग में वैज्ञानिकों और नीतिकारों ने इस बात पर चर्चा की। इस मीटिंग में हुई चर्चा का सार यह है कि जैव विविधता को बचाने के एक दूरगामी दृष्टि ज़रूरी है जिसमें 2050 तक प्रजातियों की विलुप्ति पर रोक लगाना शामिल हो। इसके लिए एक संधि का मसौदा तैयार करने हेतु जापान के नागोया शहर में अगली मीटिंग की तैयारी हो रही है। उक्त बैठक में लगभग सभी सहमत थे कि 2002 के सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में खास प्रगति नहीं हुई है।

बैठक के दौरान जिस कार्य योजना पर चर्चा हुई उसमें सन 2020 के लिए 20 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि सभी लोग जैव विविधता की महत्ता और इसे बचाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के प्रति सजग हों।

अन्य लक्ष्यों में शामिल हैं - जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाली सबसिडी को बंद करना और खेती-बाड़ी, जंगलों और एक्वाकल्चर का प्रबंधन टिकाऊ ढंग से करना। लेकिन इन लक्ष्यों को लेकर कई प्रश्न भी हैं।

यूरोपियन कमीशन में जैव विविधता के कार्यनीति अफसर नाटाली पॉवेल्स का कहना है कि यह भी सामान्य सहमति थी कि 2050 के लिए एक दूरगामी योजना से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी कि क्या किया जाना चाहिए मगर उनका कहना है कि इस समझौते में कोई ठोस लक्ष्य उभरकर नहीं आ रहे हैं।

कुछ लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लक्ष्य रखे जाएं और कौन-से निर्णय अलग-अलग देशों पर छोड़े जाएं। उनका कहना है कि इस समझौते पर और चर्चा की आवश्यकता है। राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम के मैट वालपोली कहते हैं कि यह एक खुला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर कितने मात्रात्मक लक्ष्य रखे जाएं। हमें जो करने की आवश्यकता है वह बहुत साफ और सुनिश्चित होना चाहिए। अभी का ड्रॉफ्ट तो बहुत ही जटिल और बारीकियों से भरा है।

ब्राज़ील की जैव विविधता व पर्यावरण सचिव मारिया सेसिलिया वे डी ब्रिटो का मत है कि सभी देशों को चाहिए कि वे जैव विविधता को बचाने के लिए खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी समझें। उनका कहना है कि इस समझौते के लिए सभी देशों की सरकारों को 2015 तक राज़ी करना होगा। और सभी देशों को भी आपस में मिल-जुलकर इसके लिए काम करना होगा। यह चर्चा फरवरी में नार्वे में होने वाली कांफ्रेंस में जारी रहेगी। ***(स्रोत फीचर्स)***